

## विधिक सहायता में जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की भूमिका

माधव शरण पाठक

सहायक प्राध्यापक विधि विभाग

श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर (मध्यप्रदेश)

विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं और न्याय के अवसर सभी को समान रूप से मिले साथ ही केवल गरीबी व पिछड़ेपन के कारण कोई न्याय प्राप्त करना से वंचित न रह जाए के लिए हमारे भारतीय संविधान के 42वे संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से अनुच्छेद 39a में निःशुल्क विधिक सहायता का लक्ष्य राज्य के लिए परिलक्षित किया गया और जिसके अंतर्गत "राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह, विशिष्टतया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

सभी के अधिकार संरक्षित व सुरक्षित रहे सभी को सस्ता सरल व सुगम न्याय प्राप्त हो व विचाराधीन मामला शीघ्र निराकृत हो व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो के लिए न्यायपालिका द्वारा समय समय पर विधिक सहायता शिविर एवं लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। न्याय को आम आदमी के लिए आसान बनाने का श्रेय पूर्व चीफ जस्टिस पीएन भगवती को जाता है साल 1979 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस भगवती ने हुसैनारा खातून मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि संविधान में सभी को गरिमा के साथ जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया है. गरीबी या अशिक्षा के कारण किसी को किसी को न्याय से वंचित नहीं रखा जा सकता है। एच हास्काट मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिक सहायता के संबंध महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए।

न्याय में देरी न्याय की हत्या जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 व लोक अदालत जैसे साधन न्याय प्राप्त करने में काफी कारगर सिद्ध हो रहे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य

विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एवं तहसील विधिक सेवा समिति का गठन सस्ता सुलभ न्याय जनता को प्रदाय करने के लिए किया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 9 एवं 10 में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन एवं कार्य के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये हैं -

#### जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

- (1) राज्य सरकार, के परामर्श से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, एक निकाय का गठन करते हैं जिसे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण कहा जाता है राज्य के प्रत्येक जिले को प्रदत्त या सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करने और कार्य करने के लिए, इस अधिनियम के तहत जिला प्राधिकरण।
- (2) एक जिला प्राधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे-
  - (ए) जिला न्यायाधीश जो इसका अध्यक्ष होगा; और
  - (बी) उतनी संख्या में अन्य सदस्य, जिनके पास ऐसा अनुभव और योग्यता हो, जितनी हो सके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित, उस सरकार के परामर्श से नामांकित किया जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश.
- (3) राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के परामर्श से, नियुक्त करेगा राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति जो अधीनस्थ न्यायाधीश या सिविल से कम रैंक का न हो न्यायाधीश को इस तरह का कार्य करने के लिए जिला न्यायपालिका के सचिव के रूप में जिला न्यायपालिका की सीट पर तैनात किया जाता है उस समिति के अध्यक्ष के अधीन ऐसी शक्तियां और कर्तव्य निभाना जो उसे सौंपे जाएं ऐसे अध्यक्ष
- (4) जिले के सदस्यों और सचिव के पद की शर्तें और उससे संबंधित अन्य शर्तें प्राधिकरण ऐसा होगा जो राज्य प्राधिकरण द्वारा परामर्श से बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ.
- (5) जिला प्राधिकरण उतनी संख्या में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अपने कार्यों का कुशल निर्वहन।

- (6) जिला प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे वेतन के हकदार होंगे और भत्ते और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों के अधीन होंगे जो राज्य द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से।
- (7) प्रत्येक जिला प्राधिकरण के प्रशासनिक व्यय, जिसमें वेतन, भत्ते और शामिल हैं जिला प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय पेंशन होगी राज्य की संचित निधि से भुगतान किया गया।
- (8) जिला प्राधिकरण के सभी आदेश एवं निर्णय सचिव अथवा किसी अन्य द्वारा प्रमाणित किये जायेंगे जिला प्राधिकरण का अन्य अधिकारी जो उस प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्राधिकृत हो।
- (9) जिला प्राधिकरण का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगी जिला प्राधिकरण में किसी रिक्ति का अस्तित्व, या उसके गठन में कोई दोष।

#### जिला प्राधिकरण के कार्य

- (1) प्रत्येक जिला प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि जिले में राज्य प्राधिकरण के ऐसे कार्यों का पालन करना जो उसे समय-समय पर सौंपे जा सकते हैं राज्य प्राधिकरण द्वारा समय.
- (2) उपधारा
  - (1) में निर्दिष्ट कार्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिला प्राधिकरण निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य कर सकता है, अर्थात्:
    - (ए) तालुक कानूनी सेवा समिति और अन्य कानूनी सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय करें जिला
    - (बी) जिले के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना; और
    - (सी) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य प्राधिकरण कर सकता है

उक्त अनुक्रम में छतरपुर में भी जिला विधिक सहायता प्राधिकरण की स्थापना की गई है सत्र 2023-24 में जिला विधिक सहायता प्राधिकार छतरपुर द्वारा लोक अदालत के माध्यम से २८०० मामला का निराकरण किया गया १०२८ विधिक सहायता शिविर लगाया गया ३१६ मामला में अभियुक्तों एवं जरूरी कार्य को विधि सहायता उपलब्धा कराई गई है तथा लोगों को विधिक

सहायता उपलब्ध करने हेतु ०५ विधिक सहायता क्लिनिक स्थापित की गई है जिला विधिक सहायता प्राधिकरण छतरपुर द्वारा न्याय को जन जन तक पहुँचाने हेतु श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के विधि विभाग लीगल एड क्लिनिक को दिनांक 27/06/2023 को स्थापित किया है आर्थिक एवं अन्य निर्योग्य व्यक्ति जो अपने अधिकारों की जानकारी नहीं रखता को जागरूक करने हेतु विधिक सहायता शिविर ग्रामीण अंचल तक लीगल एड क्लिनिक एवं जिला विधिक सहायता प्राधिकरण छतरपुर द्वारा आयोजित हो रहे हैं। जिला विधिक सहायता प्राधिकरण छतरपुर द्वारा टोल फ्री नं. 15100 एवं लीगल एड क्लिनिक द्वारा टोल फ्री नं. 6262618023 जारी किया है जिसके माध्यम से सैकड़ों लोग विधिक सेवा से लाभान्वित हो रहे हैं विवादों को सुलह के माध्यम से लोक अदालतें निपटा रही हैं। ऐसे अभियुक्त जिनके पास अपनी पैरवी हेतु वकील नहीं कर सकता उसे धारा 304 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (Section 341 of Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023) के अधीन राज्य के व्यय पर विधिक सहायता प्रदाय की जाती है। ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं और अपनी संपत्ति के संबंध में कोर्ट फीस के अदा नहीं कर सकते उन्हें व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन आदेश 33 के अधीन अकिंचन वाद के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। भारतीय संविधान में व्यक्ति में केवल जीवन का अधिकार समाहित नहीं वरन् मानव गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार समाहित है जिसे न्यायपालिका द्वारा समय समय पर अनुच्छेद 32 व 226 के अंतर्गत संरक्षण प्रदान किया जाता है। विधिक सहायता के अनवरत प्रयासों से न्यायपालिका के प्रति जनसामान्य की आस्था बढ़ी है और न्याय पालिका के प्रति व्यक्ति का विश्वास अतुल्य है और जहाँ भी कहीं किसी व्यक्ति के अधिकारों पर प्रश्नचिन्ह उठता है तो वह यही कहता है :

**"I WILL SEE YOU IN THE COURT"**

### **चैक बाउंस प्रकरण**

आज के समय में अधिकांश लोग लेनदेन या व्यवसाय में चैक का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग अकाउंट में उपलब्ध राशि से अधिक राशि का चैक जारी कर देते हैं और वह चैक अपर्याप्त राशि या किसी अन्य कारण से अनादरित कर दिया जाता है जिसे आम बोलचाल की भाषा में चैक बाउंस कहते हैं जिसे परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 में विस्तार से बताया गया है।

यदि किसी खाता धारक द्वारा कोई ऐसा चैक जारी किया जाता है जो अपर्याप्त राशि या अन्य कारण के द्वारा बैंकर द्वारा राशि आहरण नहीं किया जाता है और बैंकर द्वारा इस संबंध में बाउंस या अनादरण का प्रमाण पत्र दिया जाता है लेकिन चैक बैंक के समक्ष चैक लिखे जाने के 6 माह के अंदर या विधिमान्य अवधि में प्रस्तुत की जानी चाहिये। वह व्यक्ति जिसे चैक जारी किया गया था खाता धारक को 30 दिन की म्यादी सूचना एडवोकेट के माध्यम से देगा और यदि म्यादी सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर राशि खाता धारक को प्रदाय नहीं की जाती तब चैक धारक न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर चैक में उल्लिखित राशि खाता धारक से प्राप्त कर सकता है जो चैक अनादरण का अपराध कारित वह चैक की राशि के दो गुने जुर्माने या दो वर्ष के कारावास से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। (धारा 138 परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881)

चैक के संबंध में न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि चैक धारक द्वारा किसी ऋण या दायित्व से पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्राप्त किया गया। (धारा 139 परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881)

यह परिवाद किसी भी स्टेज पर राजीनामा योग्य होता है। (धारा 147 परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881)

इन प्रकरणों को न्यायालय 6 माह के अंदर निपटाने का प्रयास करेंगे। (धारा 143(3) परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881)

यह मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारणीय होते हैं। (धारा 143(1) परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881)

वर्ष 2018 में हुए संशोधन के अनुसार आरोप विरचित किए जाने पर आरोपी को न्यायालय परिवादी को अंतरिम प्रतिकर के रूप में चैक की राशि का 20% संदत्त करने के लिए आदेशित करेगा। (धारा 143a परक्रम्य लिखत अधिनियम 1881)

**प्रथम सूचना रिपोर्ट**

सूचना रिपोर्ट और बोलचाल की भाषा में एफ आई आर एक सूचना है जिसे फरियादी या पीड़ित पक्षकार मौखिक या लिखित रूप में आरक्षी केन्द्र या थाने में किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने का संबंध आरोपी का विरुद्ध प्रस्तुत करता है। जिसका संबंध में विधिक प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में लेख किए गए हैं।

आमजन मानुष में यह समस्या सामान्य है कि पुलिस थाने में उनकी रिपोर्ट राजनीतिक दबाव या रिश्वत के कारण लेख नहीं की जाती जिसके निदान के लिए यह आर्टिकल विधिक सलाह के रूप में द्वारा लेख किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार शारीरिक या सांपत्तिक हानि अन्य व्यक्ति को पहुंचाता है तो राज्य का दायित्व है वह उस पीड़ित को विधि के माध्यम से उपचार प्रदान करे। यदि पीड़ित व्यक्ति अपनी शिकायत संज्ञेय अपराध यानि गंभीर प्रकृति का अपराध के संबंध कोई सूचना थाना में देता है तो थाना प्रभारी या उसके निर्देश अन्य पुलिस आफिसर रिपोर्ट लिखने को बाध्य है यहाँ तक उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार फोन के माध्यम से संज्ञेय अपराध के संबंध में रिपोर्ट दर्ज की जा सकती है।

यदि अपराध महिला संबंधी तब वह महिला पुलिस आफिसर के द्वारा लेख की जाएगी। यदि पुलिस आफिसर या थाना प्रभारी रिपोर्ट लेख नहीं करता है या इंकार करता है तब पीड़ित की अधिकार है कि वह जिले के पुलिस अधीक्षक सामान्य भाषा में कहे तो एस पी महोदय के यहाँ शिकायत आवेदन कर सकता है। (धारा 154(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973) उसके बावजूद पुलिस प्रशासन कार्यवाही नहीं करता तब आवेदनों की रिसीप्ट के आधार पर व संबंधित साक्ष्य के साथ न्यायालय में परिवाद या न्यायालय के समक्ष शिकायत प्रस्तुत कर सकता है (धारा 190(1) (a) दंड प्रक्रिया संहिता 1973)। इस दौरान ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि मार पीट का मामला है तो घटना के तुरंत बाद अपना चिकित्सकीय परीक्षण जरूर कराना चाहिए। शिकायत के परीक्षण पश्चात न्यायालय स्वयं मामले में कार्यवाही कर सकता है (धारा 200 से 203 दंड प्रक्रिया संहिता 1973) या धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन संज्ञेय मामलो में अन्वेषण के आदेश कर सकते हैं।

इस प्रकार यदि आपकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी जा रही तब आप एस पी आफिस और न्यायालय की सहायता से अपराधी को दंड दिला सकते हैं। प्रकरण में एडवोकेट (न्यायालय के अधिकारी) की सलाह भी लेना उचित होगी।

### **महिलाएं एवं भारतीय विधि**

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात् जहां महिलाओं का सम्मान होता है वहां ईश्वर निवास करते हैं यह हमारी भारतीय संस्कृति है। रामचरितमानस में किष्किंधाकांड में श्री राम ने बालि वध पर कहा था -

"अनुज वधु भग्नि सुत नारि। सुनु सठ कन्या सम ए चारि॥

इन्हहि कुदृष्टि विलोकहु जोई। ताहि वधै कछु पाप न होहि॥

संक्षेप कहा जाए यदि कोई महिलाओं को कुदृष्टि से देखे भी तो उसका वध करने पर कोई पाप नहीं लगता। महाभारत काल में द्रौपदी के अपमान पर कुरुक्षेत्र में कुरु वंश का संपूर्ण नाश हुआ। इतिहास के पन्ने उलटने पर यह स्पष्ट है कि नारी जाति का अपमान रावण, बालि, कंस, दुर्योधन की समूल मृत्यु का कारण बना।

विश्व स्तर पर संयुक्तराष्ट्र संघ के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए मानव अधिकारों एवं विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। भारतीय विधि में संविधान में, दंड विधि में, व्यक्तिगत विधियों में विशिष्ट रूप प्रावधान किए गए हैं यहां इस लेख के माध्यम से उन प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है जो आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को जानना नितान्त आवश्यक है -

(1) महिला एवं संविधान:- भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक प्रावधान किए गए हैं जिनमें अनुच्छेद 15 एवं 16 में महिलाओं को पुरुषों के समकक्ष लाने के लिए राज्य को विशिष्ट विधि बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 42 में प्रसूती सहायता प्रावधान बनाने राज्य को नीतियां बनाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं इसके अलावा केन्द्र, राज्य एवं न्याय पालिका में महिलाओं के विशिष्ट आरक्षण प्रदान किए गए हैं।

(2) महिला एवं दंड विधि:- दंड विधि के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता 1860 में महिला संबंधी अपराध अध्याय 20 धारा 493 से 498 तक (द्विविवाह, जारकर्म एवं अन्य अपराध) उल्लिखित है अध्याय 20(क) धारा 498 (क) पति एवं उसके नातेदार द्वारा महिलाओं के साथ की जाने वाली मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक क्रूरता के संबंध में दंड प्रावधानों का उल्लेख है जिसका प्रयोग महिलाओं द्वारा पुलिस रिपोर्ट या सीधे न्यायालय में परिवाद फाइल कर किया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के साथ शारीरिक रूप से, इंटरनेट, फेसबुक या अन्य सोशल साइट के माध्यम से किए जाने वाले छेड़छाड़ के मामलों को धारा 354A, 354B, 354C एवं 354D के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट या परिवाद के माध्यम से न्यायालय में दर्ज कराए जा सकते हैं। बलात्कार संबंधी अपराध धारा 376 के माध्यम से दर्ज किए जाते हैं अवयस्क पीड़िता की दशा में पाक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामले में दर्ज होते हैं जिनमें जमानत अभियुक्त प्राप्त होना बिरलतम से बिरलतम दशा में प्राप्त होती है। धारा 304 ख विवाह के सात सालों के भीतर होने वाली वधु की मृत्यु के संबंधी अपराध एवं दंड के बारे में प्रावधान करती है। भ्रूण हत्या संबंधी अपराध धारा 312 से 318 तक प्रावधानित हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 पत्नि व माता को भरण पोषण के अधिकार का प्रावधान तथा धारा 154 महिलाओं की रिपोर्ट महिला पुलिस अधिकारी पूर्ण शिष्टता के साथ लेख करने का प्रावधान करती है इसके अलावा महिलाओं संबंधी अपराधों का विचारण जहां तक संभव महिला जज के माध्यम से सुने जाने का प्रावधान भी करती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 113(ख) एवं 114(क) न्यायालय को महिला संबंधी अपराधों में विशिष्ट उपधारणा करने को निर्देशित करती है।

(3) महिला एवं व्यक्तिगत विधि:- व्यक्तिगत विधियों में महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है जैसे हिंदू विवाह अधिनियम 1956 में धारा 9 न्यायिक पृथक्करण, दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद, भरण पोषण एवं द्विविवाह आदि। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा शायरा बानो के मामले तीन तलाक की कुप्रथा को शून्य घोषित किया गया है।

यदि महिलाओं के विरुद्ध पूरे देश में दर्द अपराधों पर एक नजर दौड़ाई जाए तो आंकड़े डराने वाले ही हैं।

(क) वर्ष 2015 में महिलाओं के विरुद्ध मामले 3,27,394



(ख) वर्ष 2017 में 3,59,849

(ग) वर्ष 2018 में 3,78,236

(घ) वर्ष 2019 में 4,05,861

वर्ष 2019 के इन मामलों को वर्गीकृत किया जाए तो

बलात्कार मामले 32,033

बलात्कार के प्रयत्न मामले 4038

यौन उत्पीड़न एवं लज्जा भंग मामले 88,387

स्त्री लज्जा अनादर मामले 6939

पाक्सो एक्ट 46,056

साइबर क्राइम 1645 दर्ज हुए हैं।

हाल ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध को गंभीरतापूर्वक लेते हुए दिनांक 18 मार्च 2021 को अपर्णा भाट और अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं एक अन्य AIR 2021 SC 1492 के मामले में निर्णीत किया है कि "विधि ऐसी शर्तों पर जमानत प्रदान करने की अनुमति नहीं देता जिससे उचित विचारण की प्रक्रिया प्रभावित हो। अभियुक्त, पीड़िता से राखी बंधवाए, पीड़िता से शादी करे, कोविड योद्धा के रूप में पंजीकृत हो, सुलह करे आदि शर्तों पर जमानत प्रदान किया जाना न्यायालय को किसी दांडिक अपराध में विरोधी के बीच में न्याय के पुनः वार्ता और सुलह के प्रति और जेंडर स्टीरियोटाइप्स के प्रति संदेहास्पद बना देता है। स्टीरियो टाइपिंग महिला के एक उचित विचारण को प्रभावित करता है।"

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विधि और विधानों ने मातृशक्ति को सुरक्षित कर रखा है लेकिन आवश्यकता है हमारे समाज की मनोदशा के परिवर्तन की जो नारी और पुरुष की समकक्षता को स्वीकार करे।

**॥हे मातृशक्ति बारंबार नमन है आपको॥**